भारत - लाओस संबंध

ऐतिहासिक एवं सभ्यतागत नींव तथा भारत - चीन पर अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण आयोग (आई सी एस सी) के अध्यक्ष के रूप में भारत द्वारा निभाई गई भूमिका के आधार पर भारत और लाओ जनवादी लोकतांत्रिक गणराज्य (पी डी आर) के बीच पुराने, मैत्रीपूर्ण तथा परस्पर सहयोगात्मक संबंध हैं। लाओ पीडीआर भारत के लिए अंतर्राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय सरोकार के प्रमुख मुद्दों पर भारत का समर्थन करता है जिसमें संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थाई सदस्यता के लिए हमारी दावेदारी शामिल है।

राजनीतिक संबंध : राजनयिक संबंध फरवरी 1956 में स्थापित हुए। तब से दोनों देशों के बीच निम्नलिखित उच्च स्तरीय यात्राओं से यह संबंध और मजबूत हुआ है : प्रधानमंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू ने 1954 में, प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने 2002 में, प्रधानमंत्री डा. मनमोहन सिंह ने आसियान शिखर बैठक के लिए 2004 में, राष्ट्रपति डा. राजेन्द्र प्रसाद ने 1956 में, राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटील ने सितंबर 2010 में, श्री मोहम्मद हमीद अंसारी ने सितंबर, 2015 में लाओ पीडीआर दौरा किया। लाओ पी डी आर की ओर से प्रिंस सोउफानुवोंग, जिनको आमतौर पर रेड प्रिंस के नाम से जाना जाता है, ने 1975 में भारत का दौरा किया, राष्ट्रपति श्री चोमलाई सायासोने ने अगस्त 2008 में प्रधानमंत्री श्री थोंगसिंग थम्मावोंग ने 20 और 21 दिसंबर 2012 को भारत का दौरा किया।

संस्थानिक परामर्श तंत्रों में विदेश कार्यालय परामर्श (दूसरे विदेश कार्यालय परामर्श का आयोजन नई दिल्ली में अगस्त 2015 को हुआ) और जे सी एम (8वें जे सी एम का आयोजन नई दिल्ली में 10 अगस्त 2015 को हुआ) शामिल हैं।

जिन करारों पर दोनों देशों के बीच हस्ताक्षर किए गए हैं उनमें निम्नलिखित शामिल हैं **:** भारत - लाओस सांस्कृतिक करार (अगस्त 1994), व्यापार, आर्थिक और वैज्ञानिक सहयोग पर संयुक्त आयोग के गठन के लिए करार - मई 1997, निम्नलिखित पर करार (i) व्यापार एवं आर्थिक सहयोग; और (ii) द्विपक्षीय निवेश संवर्धन एवं संरक्षण (9 नवंबर 2000), रक्षा में सहयोग पर करार (नवंबर 2000), विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में सहयोग पर करार (जून 2003), राजनयिक एवं आधिकारिक पासपोर्ट धारकों के लिए वीजा की आवश्यकता से छूट पर करार (2005)।

रक्षा सहयोग : वर्ष 1994 से भारतीय तकनीकी एवं आर्थिक सहयोग (आई टी ई सी) करार के तहत एक भारतीय सेना प्रशिक्षण दल अंग्रेजी, कंप्यूटर एवं बुनियादी रण कौशलों में लाओस के रक्षा कार्मिकों के लिए प्रशिक्षण का संचालन करती है। वियतनाम एवं चीन की टीमों के अलावा भारतीय टीम एकमात्र विदेशी टीम है। भारतीय सेना ने 2011, 2012 और 2013 में लाओस में यू एक्स ओ तथा बारूदी सुरंग हटाने पर तीन प्रशिक्षण कैप्सूल का भी आयोजन किया था।

वाणिज्यिक संबंध :

द्विपक्षीय व्यापार :

	2009-2010	**2010-2011**	**2011-2012**	**2012-2013**	**2013-2014**
निर्यात	16.93	13.11	14.97	28.91	49.89
आयात	20.05	0.22	89.53	138.64	39.40
कुल व्यापार	36.98	13.33	104.50	167.56	89.29

स्रोत *:* वाणिज्य विभाग, भारत सरकार (आंकड़े मिलियन अमरीकी डालर में)

भारत और लाओ पीडीआर के बीच मुख्य रूप से मेटल, अयस्क, मशीनरी, इलेक्ट्रानिक उपकरण, भेषज पदार्थ तथा टिम्बर आदि का व्यापार होता है। अप्रैल, 2008 में भारत के प्रधानमंत्री द्वारा की गई घोषणा के अनुसरण में भारत ने लाओ पी डी आर को ड्यूटी फ्री टैरिफ प्रिफरेंस स्कीम (डी एफ टी पी) प्रदान की है। यह स्कीम लाओस को भारत की कुल टैरिफ लाइनों में से 94 प्रतिशत पर ड्यूटी फ्री अक्सेस प्रदान करती है।

विदेश प्रत्यक्ष निवेश (एफ डी आई) : 161 मिलियन अमरीकी डालर के निवेश तथा कुल 33 परियोजनाओं के साथ लाओस में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की दृष्टि से भारत आठवें स्थान पर है। कुछ प्रमुख भारतीय निवेश इस प्रकार हैं : (i) जून 2006 में स्थापित बिड़ला लाओ पल्प एण्ड प्लांटेशन सवानाखेत प्रांत में यूकेलिप्टस पल्प एण्ड प्लांटेशन परियोजना में 400 मिलियन अमरीकी डालर का निवेश करने के लिए प्रतिबद्ध है; (ii) लाओ एस पी जी सी एम सी माइनिंग कंपनी लिमिटेड, जो जिमपेक्स इंडिया की एक सहायक कंपनी है, ने 10 मिलियन अमरीकी डालर का निवेश करने की प्रतिबद्धता के साथ 2008 में एक लौह अयस्क खदान के लिए लाइसेंस प्राप्त किया और (iii) एच एस एम एम ग्रुप ने वियेनटेन एवं शेसोम्बुन, वियेनटेन प्रांत में दो कारखानों तथा अगरवुड प्लांटेशन में 13.8 मिलियन अमरीकी डालर का निवेश किया है।

ऋण सहायता के तहत परियोजनाएं : पिछले कुछ वर्षों में भारतीय ऋण सहायता के माध्यम से निम्नलिखित परियोजनाओं के लिए सहायता प्रदान की गई है :

1. चंपासाक प्रांत में बान-ना से अट्टापेऊ तक 115 के वी की पारेषण लाइन के लिए 10 मिलियन अमरीकी डालर की ऋण सहायता (2004) - जिसे 2006 में पूरा किया गया

2. निम्नलिखित के लिए 33 मिलियन अमरीकी डालर की ऋण सहायता (क) ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए उपकरण, (ख) पाकसन - जेंगसाई बैंजियो पारेषण लाइन और (ग) 7.5 मेगावाट की नाम सोंग जल विद्युत परियोजना (2008) - जिनको क्रमश: 2009, 2010 और 2012 में पूरा किया गया।

3. चंपासक प्रांत में सिंचाई की स्कीमों के लिए 17.3 मिलियन अमरीकी डालर की ऋण सहायता - जिसमें 3 घटक शामिल हैं : (क) डीजल से चलने वाले पंप सेट को बिजली से चलने वाले पंप सेट में परिवर्तन करना तथा 3 पंप स्टेशनों का सुधार, (ख) दस बड़े पंप सेट लगाना और (ग) सिंचाई की छ: बड़ी स्कीमें (2009) - जिसे 2014 में पूरा किया गया

4. नबोंग से थबोक तक 230 के वी की डबल सर्किट पारेषण लाइन और उप केन्द्र के लिए 37.30 मिलियन अमरीकी डालर की ऋण सहायता (2010) - जिसे 2015 में पूरा किया जाना है

5. तीन प्रांतों में सिंचाई परियोजनाओं के लिए 30.94 मिलियन अमरीकी डालर की ऋण सहायता (2013) - चल रही है।

सांस्कृतिक संबंध :

मानव संसाधन विकास : भारत सरकार विभिन्न स्कीमों के तहत लाओस के नागरिकों को 200 से अधिक छात्रवृत्तियां प्रदान कर रही है। अब तक, भारत सरकार द्वारा आई टी ई सी के तहत लाओस के लगभग 1500 नागरिकों को प्रशिक्षण दिया गया है। नवंबर 2004 में स्थापित लाओ - भारत उद्यमशीलता विकास केन्द्र (एल आई ई डी सी) लघु एवं मध्यम स्तर पर कारोबार स्थापित करने के लिए लाओस के उद्यमियों को प्रशिक्षित करता है। जून 2007 में वियनटेंन में स्थापित लाओस - भारत अंग्रेजी भाषा प्रशिक्षण केन्द्र (एल आई सी ई एल टी) मानव संसाधन विकास में हमारी सहायता परियोजनाओं में से एक है। भारत ने नवंबर, 2004 में विएनटेन में एक आईटी केंद्र तथा

मई, 2006 में एक राष्ट्रीय डाटा केंद्र का गठन किया। दस ग्रामीण दूर संचार केंद्र - सात प्रांतों में तथा स्वास्थ्य मंत्रालय, सरकारी कार्यालय तथा विएनटेन के राज्यपाल के कार्यालय में तीन – स्थापित किए गए हैं।

विरासत का संरक्षण : वाट फू में विश्व विरासत स्थल के जीर्णोद्धार के लिए मई, 2007 में सूचना एवं संस्कृति मंत्रालय के साथ एक एम ओ यू पर हस्ताक्षर किया गया। जून, 2009 में परियोजना पर कार्य शुरू हो गया। आठ साल की अवधि में भारत इस परियोजना पर 4.1 मिलियन अमरीकी डालर खर्च करेगा।

भारतीय समुदाय :

पिछले वर्षों में 400 भारतीय समुदाय ने अपनी प्रोफाइल का मजबूती से विकास किया है। भारतीय समुदाय ज्वेलरी के व्यापार, रेस्टोरेंट एवं होटल उद्योग, विनिर्माण, गारमेंट, खनन, प्लांटेशन तथा अगरवुड के कारोबार में लगा हुआ है। कुछ सदस्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों, बहुराष्ट्रीय कंपनियों, परामर्शी संगठनों तथा निजी व्यवसायों के लिए काम करते हैं। ऐसा समझा जाता है कि 6वीं एवं 7वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में लाओस में भारतीयों की संख्या अधिक थी। वियेनटेन में एक मात्र भारतीय एसोसिएशन इनचैम - दि इंडियन चैंबर ऑफ कामर्स है। इसके वर्तमान अध्यक्ष श्री सुभाष भार्गव हैं, दूरभाष : 00856-20-55500611 हालांकि इसके तहत लाओस में रहने वाले सभी भारतीय शामिल नहीं हैं तथा यह बहुत सक्रिय नहीं है, यह इस देश में रहने वाले भारतीयों एवं पी आई ओ के लिए एक मात्र छत्रछाया है।

उपयोगी संसाधन :

भारतीय दूतावास, विएनटेन की वेबसाइट :
http://indianembassylaos.org

भारतीय दूतावास, विएनटेन का फेसबुक पेज:
https://www.facebook.com/India.in.Laos

***

जनवरी**, 2016**